

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनियों आर.ए.एस

अपील सं० 2016/00255 (15/2016)

जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर । -अपीलान्त

बनाम

1. लूण सिंह पुत्र स्व भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ । (राज०)
2. कान सिंह } पि० भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील
3. प्रभू सिंह } नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर । -रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2007

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्र० संख्या 87/2007 बअनवान लूण सिंह बनाम जगदीश

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलान्त

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं० 1, 2, 3

निर्णय

दिनांक - 12.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोजेण्ट सं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद में कथन किया कि रोही मौजा मेघाना में कुल 968.07 बीघा भूमि मृतक मघसिंह, भूर सिंह, पि० हरिसिंह व मु० जुहारा बेवा प्रताप सिंह, सुगन. सिंह पुत्र हरनाथ सिंह अकवाम राजपूत साकिन मेघाना की मुश्तरका खातेदारी भूमि थी। उपरोक्त भूमि में से जुहारासिंह ने दिनांक 25.09.1962 को ख. नं. 25/6/1 की

*Lois*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



तादादी 30.01 बीघा व 25/8 की 43.11 बीघा कुल 73.12 बीघा भूमि वादी के पिता भोपाल सिंह की विक्रय कर दी। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 3 की माता मानी देवी ने मु० जुहारा से ख. नं. 195 की 31.19 बीघा व ख. नं. 185/2 की 15.12 बीघा कुल 47.11 बीघा दिनांक 25.09.1962 को बैय की। इस प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पिता भोपाल सिंह के पास 73.11 बीघा व प्रतिवादी सं० 4 मानी देवी के पास 47.11 बीघा कुल 121.03 बीघा भूमि के खरीदशुदा खातेदार काश्तकार हुए। भोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता की खातेदारी भूमि में जिसमें 35.00 बीघा भूमि बैय कर दी शेष 38.12 बीघा भूमि जिस पर पहले वादी के पिता अब उनके वारिस प्रतिवादी सं० 2 ता 4 काबिज हैं लगातार कब्जा काश्त में है, जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है, परन्तु वरवक्त पैमाईश भू-प्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 1 क नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है ना ही उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार है। उसके पास उक्त भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। वाद भूमि वादी के पिता की मोरूसी भूमि है। अतः प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10.12 बीघा भूमि कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी ने दावा पेश करके अपीलाण्ट का बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो अपीलाण्ट के हितों के मुकाबले शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है तथा लगातार कबिज चला आ

Lario  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



रहा ह फिर भी मातहत अदालत ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य व बिना पटवारी की रिपोर्ट तथा बिना सुनवाई किये मनमाना निर्णय पारित करके भारी भूल की है। विवादित भूमि 868 बीघा का एकल खेत है। मौका खसरा किस खसरे में बना है तथा किसके कब्जा में है बिना जांच पड़ताल किये मात्र वादी के मौखिक कथनों के आधार पर दावा डिक्री है जो अपीलाण्ट के हितों के खिलाफ है। निर्णय से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया मात्र नोटिस पर अपने किसी परिचित के हस्ताक्षर कवाकर माता को देना तथा चस्पा लिखकर विधि विरुद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करके निर्णय पारित किया है। अपीलांट को इस दावा बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलांट को निर्णय बाबत ज्ञान नहीं था क्यों कि विवादित भूमि पर आज भी अपीलांट का कब्जा काशत है दिनांक 25.03.2016 को पटवारी हल्का से अपनी भूमि की पैमाईश करवाने बाबत नकल जमाबंदी लेने गया तो उक्त दावा के निर्णय बाबत पता चला जिससे तुरन्त बाद बिना किसी देरी के यह अपील पेश की है। अपीलांट एक ग्रामीण व खेतीहर सिधा साधा किसान है एवं इस निर्णय बाबत ज्ञान नहीं था इसलिए बिना ज्ञान तथा सुनवाई के पारित निर्णय से अपीलांट के हितों का हनन होता है। इसलिए अज्ञानतावश हुई देरी को माफ करके अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानते हुए सुनवाई की जावे। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।



4. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पिता भोपाल सिंह के पास 73.11 बीघा व प्रतिवादी सं० 4 मानी देवी के पास 47.11 बीघा कुल 121.03 बीघा भूमि के खरीदशुदा खातेदार काशतकार हुए। भोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता की खातेदारी भूमि में जिसमें 35.00 बीघा भूमि बैय कर दी शेष 38.12 बीघा भूमि जिस पर पहले वादी के पिता अब उनके वारिस प्रतिवादी सं० 2 ता 4 काबिज हैं लगातार कब्जा काशत में है,

*Levio*  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 हनुमानगढ़

जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है, परन्तु वरवक्त पैमाईश भू-प्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है ना ही उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार है। उसके पास उक्त भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। वाद भूमि वादी के पिता की मोरूसी भूमि है। अतः प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10.12 बीघा भूमि कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिये गये थे मगर अपीलाण्ट तामील के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2007 को पारित की गई थी उसकी अपील अपीलाण्ट ने लगभग 15 वर्ष बाद पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। दरखास्त की मद सं० 2 मनबगढंत गलत बयानी स्वीकार नहीं है। जामबन्दी ऑन लाईन कभी भी ल जा सकती है पटवारी का कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान था तथा 15 वर्षों की लम्बा विलम्ब माफी योग्य नहीं है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर बिना सन्तोषप्रद कारण प्रकट किये इतनी देरी से अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट करना चाहिए मात्र जमाबन्दी पटवारी से लेने का आधार पर पता चलना वो भी 15 वर्षों बाद मात्र सुसंगत आधार नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र एवं अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 आरबीजे पेज 20, 2009 आरआरटी पेज 488, 2016 आरएलडब्ल्यू पेज 1, 1998 आरबीजे पेज 274, 1994 आरअबीजे पेज 231 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

*Levin*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट सं० 1 ने राजस्थान कातशकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें वरवक्त पैमाईश भू-प्रबन्ध विभाग ने प्रशगनत भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम गलत रूप से दर्ज करने एवं प्रतिवादी का उस भूमि पर कब्जा नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2007 के द्वारा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया था जो चस्पांदगी से तामील किया गया है। उसके बाद दिनांक 26.06.2007 को दैनिक अखबार में सम्मन साया करने के आदेश दिये गये। अखबार में सम्मन साया करने के उपरान्त अखबार की प्रति पेश हुई अपीलाण्ट के उपिस्थत नहीं आने के बाद उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.08.2007 को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद डिक्री किया गया है। दिनांक 20.08.2007 के निर्णय की अपील अपीलाण्ट ने दिनांक 06.04.2016 को लगभग 9 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा अपील इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त संतोषजनक कारण नहीं बताया है। आरआरटी 2009 (1) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "विलम्ब शमन के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिया— अपील बुरी तरह से कालातीत है एवं खारिज योग्य है।" इस प्रकरण में भी अपीलाण्ट ने लगभग 9 वर्ष बाद यह अपील पेश की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है। इतना लम्बा विलम्ब बिना किसी पर्याप्त कारण के क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।



*Levis*  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Lesio*  
12/1/23  
( करतारसिंह पूनियाँ )  
आर.ए.एस  
राजस्थान अपील अधिकारी  
हनुमानगढ़